

ENQUIRY RE CALLING ATTENTION NOTICE

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, हमने आज एक ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उस सम्बन्ध में जब मैं लखनऊ से आया तो 9 बजे मैंने रेल मंत्री श्री घोष जी और घर मंत्री श्री वाई० बी० चव्हाण साहब से भी बात कर ली थी, उनको सूचित कर दिया था कि ऐसी घटना घटी, ताकि वे यह न कहें कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। दो घंटे का पूरा समय था। पहले मैं कार्लिंग अटेंशन नोटिस ही पढ़ देता हूँ। कल 6-12-67 को लखनऊ दिल्ली मेल से जब मैं आ रहा था तो चार बार रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के जवानों ने विद्यार्थियों पर बुरी तरह लाठी चार्ज किया और बहुत से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। मैं डिब्बे के बाहर से जो दरोगा छात्र को पीट रहा था, उनको मना कर रहा था कि इनको क्यों पीट रहे हो, इनका क्या कसूर है। तो रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे प्लेटफार्म पर जिस ढंग से निरंकुश, बर्बर लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

माननीया, मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूँ और आपके द्वारा सदन को कि मैं 9 बजे कर 20 मिनट पर रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचा...

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): Madam, under what particular rule is my hon. friend moving this particular motion?

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is not moving any motion.

DIWAN CHAMAN LALL : What is he making, a speech?

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Chairman has allowed him to mention this just now at 2.30. Since the Chairman has agreed that he should mention it, I am allowing him.

DIWAN CHAMAN LALL : All that I am asking is, if the Chairman has allowed Mr. Rajnarain, under what particular rule has he allowed it ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Chairman has allowed him. Let him say.

श्री राजनारायण : दिवान चमन लाल जी हैं तो कुछ पुराने लेकिन नये की तरह काम कर रहे हैं। हां तो, माननीया, मेरा निवेदन यह था कि 9 बजे कर 20 मिनट पर मैं जब पहुंचा तो वहां पर विद्यार्थी थे, हो सकता है कि 400 या 500 रहे हों या ज्यादा रहे हों, मगर तीन आवाजें हमने सुनीं, 'अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से मुल्क गुलाम नहीं होगा' 'छात्र किसान और मजदूर कर देंगे अंग्रेजी चूर', 'अंग्रेज यहां से चले गये, अंग्रेजी हमें हटानी है'। इन तीनों नारों में एक भी ऐसा नारा नहीं था जो असंवैधानिक हो, यह सही है कि जब मैं पहुंचा तो कुछ लोगों ने हमारा भी नाम ले कर जिन्दाबाद का नारा लगाया। मैं ट्रेन पर चढ़ गया और मैं ताज्जुब से देखता हूँ, दरवाजे पर खड़े हो कर कि रेलवे पुलिस के जवान मोटी मोटी लाठी ले कर के लगे लड़कों पर बरसाने, एक बालक को पकड़ लिया और मैं दरवाजे पर खड़ा कह रहा था, उस दरोगा से जो कि लड़के को पीट रहा था कि इसको मत मारो, मत मारो। उसको दो डंडा मारा, पहला मारा तो मैंने रोका दरवाजे के बाहर खड़े-खड़े लेकिन जब दूसरा मारा तो मैं दरवाजे से नीचे कूद कर आ गया, तो उसको खींच कर बाहर ले जाया गया, कहां ले गये पता नहीं। मैंने कहा कि जब तक वह लड़का नहीं आवेगा तब तक ऐसा लगता है कि यहां के अधिकारी चाहते हैं कि ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाय। यह सही है, फिर हमने लोगों से कहा कि ट्रेन बढ़ने नहीं पाये जब तक गैरकानूनी ढंग से बर्बरता के साथ विद्यार्थियों पर जो लाठी चली है उस सम्बन्ध में अधिकारियों की कोई सफाई न आ जाय।

[श्री राजनारायण]

तो, माननीया, मैं आपके जरिये सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा हुआ कि नेता सदन में आ गये हैं, वह विद्यार्थियों, मजदूरों के सम्बन्ध में हमदर्दी रखते हैं, उनकी समस्या को भी कुछ जानते हैं, समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि मान लीजियेगा कोई मुझे रेल पर चढ़ाने आये और रेल पर चढ़ाने वालों की कुछ सौ पचास या बीस की भीड़ हो तो उन पर डंडा चलाने का हक सरकार को कैसे है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने उन पर डंडा कैसे चलाया, क्यों चलाया? यह सवाल आज केवल भाषा से ही सम्बन्धित नहीं है, यह सवाल जहाँ अंग्रेजी को हटाने का है, वहाँ ही अपने नागरिक अधिकारों और मानवीय अधिकारों की सुरक्षा का भी है, साथ-साथ दोनों एक दूसरे से सने हुये हैं। तो मैं बहुत ही अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार इसके सम्बन्ध में पूरी इन्क्वायरी कराये, पूरी जाँच पड़ताल कराये और इस सदन में एक व्यापक बयान दे, चाहिये कि अभी दे, हमारे नेता सदन को मालूम होगा, हमने रेल मंत्री और घर मंत्री को पहले खबर कर दी थी कि उन्हें आज सदन में रहना चाहिये। आज जब कि सारा देश एक क्षोभ की ज्वाला में जल रहा है इस भाषा के सवाल को ले कर तो अनावश्यक ढंग पर यह रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स छात्रों पर डंडा लाठी चला कर उत्तेजना पैदा करे? मैं नहीं चाहता कि इस ढंग से उत्तेजना पैदा कराई जाय।

माननीया, इसी तरह से अभी-अभी आपके सामने बैठा था कि पता चला कि यहाँ पर दिल्ली के विद्यार्थियों पर डंडा चल गया, कहीं आग लग गई, तो जानबूझकर यह सरकार आज इस देश को अग्नि की ज्वाला में झोंक रही है। सरकार को चाहिये कि सीधे-सीधे एलान कर दे। हमको

अभी अभी कांग्रेस पक्ष के एक सम्माननीय व्यक्ति ने बताया कि चव्हाण साहब शायद यह मान रहे हैं कि विधेयक में जहाँ लिखा है कि हिन्दी का जानना जरूरी नहीं है वहाँ यह भी बढ़ा देंगे कि अंग्रेजी का जानना जरूरी नहीं है। यह मैं मानता हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट है, एक विकास है। उसी के साथ-साथ शायद उन्होंने यह भी माना अब अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हिन्दी सूबों को तैयार करना जरूरी नहीं होगा। तो उसमें अगर समुचित और सम्यक जनमत की अपेक्षा न कर के उसकी भावना की कद्र करते हुये, सरकार कोई संशोधन को मानती हो तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को फौरन कोई डिक्लेरेशन कर देना चाहिये ताकि सारे देश में जो आग लगी है उस आग का लगना आगे न बढ़े। तो, माननीया, मैं अदब के साथ आपके जरिये सरकार से और इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज भारत का छात्र, भारत का नवयुवक जागा है, वह अंग्रेजी भाषा के विरुद्ध जागा है, जैसे अंग्रेजों को हटाया गया, अंग्रेजी को भी हटाया जायगा, इसमें दो राय नहीं हैं और अगर सरकार उचित कदम नहीं उठाती, तात्कालिक कदम नहीं उठाती तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य दूसरे सूबों में...

उपसभापति : राजनारायण जी, अब बस कीजिये।

श्री राजनारायण : माननीया, 1 मिनट और लूँगा। दस मिनट मैंने माँगे थे। हमारी नज़र बराबर घड़ी पर है। मैं आपके द्वारा श्री हाथी जी को केवल यह साफ कहना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी को पूरा...

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुख लाल हाथी) : मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं।

श्री राजनारायण : नहीं ।

श्री जयसुख लाल हाथी : जो दो बातें आपने कही हैं वह आप मुझ को कहिये ।

श्री राजनारायण : मैं अंग्रेजी को कलंक समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ, करकट समझता हूँ, गंदगी समझता हूँ । जब तक इस गंदगी को हम दूर नहीं करेंगे तब तक भारत के स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होगी । जो सामान, जो साइन बोर्ड या जो खम्भा, या जो इंजन अंग्रेजी को प्रसारित या प्रचारित करेगा उस सामग्री से अंग्रेजी को हटाने के लिये अगर उस सामग्री का भी नुकसान हो जाये तो उसको मैं अहिंसा समझता हूँ, उसको मैं राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति नहीं मानता क्योंकि मैला, पाखाना, कूड़ा-करकट को निचोड़ने, घसीटने में अगर कोई सामान, जो इसको चिपटाये हुए है, वह भी, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वह स्वाभाविक है । इन शब्दों के साथ मैं सरकार की भावना को जगाना चाहता हूँ ।

श्री एम० एम० धारिया (महाराष्ट्र) : राजनारायण जी ने जो कालिंग अटेन्शन नोटिस दिया है उसको मैंने पढ़ा नहीं मगर इन्होंने जो मांग की है इस के सिवाय ऐसा भी आज अखबारों में आया है कि राजनारायण जी जब लखनऊ में थे तब उन्होंने एक घंटा ट्रेन को लेट रखा और इंडियन एयरलाइन्स की जो बस थी उसको जबर्दस्ती अपने पार्टी आफिस ले गये जब कि उसमें और पैसेन्जर्स बैठे हुए थे । उसके बाद इन्होंने ड्राइवर को एक रुपया टिप भी दिया है । यह सब अखबारों में आया है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : You cannot take the time of the House. You are saying what has come in the Press.

श्री एम० एम० धारिया : तो इनका जो कालिंग अटेन्शन है उस पर जब कोई स्टेटमेंट आयेगा, उसके मंजूर होने के बाद, तो मंत्री जी उसमें इन सब बातों के बारे में भी बतायें कि क्या वह सही हैं ।

श्री राजनारायण : माननीया, देखिये, पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please take your seat.

श्री राजनारायण : या तो आप धारिया साहब को न कहें ।

(Interruptions)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : माननीया, मैंने भी तीन चार दिन पहले इसके ऊपर अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है, उसका आज तक हमको कोई जवाब नहीं मिला ।

उपसभापति : वह तो अभी चेयरमैन साहब देखेंगे । I I want to earnestly appeal to the House. Let us go to the regular business. Because the Chairman had permitted Mr. Rajnarain to mention this case at 2.30, I permitted him. And Mr. Rajnarain was good enough to say that he would not take very long. Well that is over Mr. Dharia, you have said something that, has appeared in the Press. Mrs. Vidyawati Chatur-vedi, your Calling Attention Notice is with the Secretariat; they are looking into it.

श्री राजनारायण : माननीया हमारा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है । जितना प्रेस में निकला है उतना ही उन्होंने नहीं कहा है, हमारे ऊपर आक्षेप किया है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : No, no. All right. Say only in one minute.

श्री राजनारायण : हां, एक मिनट में कह दूंगा । धारिया साहब ने जो कुछ भी कहा है गलत है, निराधार है और जिस प्रेस ने इसको छापा है वह प्रेस पूंजीपतियों का दलाल होगा । मैं कहना चाहता हूँ कि रेल को हमने रोका है, ट्रेन को रोका है, यह सही है और ट्रेन को हम आगे भी रोकेंगे, अगर ऐसी घटना होगी । और जहां तक हवाई जहाज के मोटर की बात

[श्री राजनारायण]
 है, वह बिल्कुल गलत और झूठ है।
 यह सही है एक रुपया हमने ड्राइवर को
 दिया।

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Madam, ... (Interruptions)

श्री राजनारायण : क्या यह मैडम-मैडम
 करते हो। बैठ जाओ। मैडम-मैडम करते-करते
 सदन का समय नष्ट करते हैं।

THE COTTON TEXTILE COMPANIES
 (MANAGEMENT OF
 UNDERTAKINGS AND LIQUIDA-
 TION OR RECONSTRUCTION) BILL,
 1967

THE DEPUTY MINISTER IN THE
 MINISTRY OF COMMERCE (SHRI
 MOHD. SHAFI QURESHI) : Madam
 Deputy Chairman, I beg to move :

"That the Bill to provide in the public interest for the liquidation of cotton textile companies while keeping the undertakings thereof as running concerns, or for the reconstruction of cotton textile companies in certain cases and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Hon. Members would recall that the Commerce Minister had on several occasions, in reply to questions and otherwise, stated in the House that he would bring forward a Bill to enable Government to take over certain weak and marginal textile mills which are considered economically viable, but which for certain reasons have been either closed or are under imminent threat of closure. He had expected to be in a position to introduce the Bill in the last session of Parliament but the finalisation of the Bill has taken longer than was initially anticipated.

As hon. Members are aware, the cotton textile industry is a very old one. In fact, it is amongst the oldest and largest organised industries in the country, dating back to more than a century. Today it consists of over 600 mills spread all over the country. It employs directly about 9,00,000 workers and indirectly about six million in the handloom and powerloom sectors to which it supplies the yarn. It is also the

principal purchaser of cotton, on which a large number of farmers depend for their livelihood. Cotton textiles have been and still are a large earner of foreign exchange.

Naturally, the problems affecting such a big and widely dispersed industry are many and complex. Moreover, speaking generally, it is considered to be a relatively low profit industry. In many cases, therefore, the entrepreneur has a tendency to withdraw funds from the cotton textile unit for reinvestment on more lucrative terms, in other enterprises. Quite a few of them are also badly sited with reference to availability of cotton, power, labour and markets. All these have reduced the productive efficiency and competitive ability for a substantial number of these mills. While these are profitable in years when cotton is plentiful and cheap and the consumer demand is strong, their profits disappear as cotton prices rise, as during the last two years, and the general purchasing power of the consuming public goes down. I might add that even in other major producing countries like Great Britain and Japan, their well-established cotton textile industries have also suffered vicissitudes of fortune. The British Government have had recently to come massively to the aid of their own textile industry for purposes of its rehabilitation; the Japanese Government is also following a somewhat similar course.

Coming back to our own immediate problem, out of the 600 odd units that we have, some 350 had been established prior to Independence and among the rest, even though these came up later, a fair proportion are actually operating with old and second-hand plant and machinery. These are the mills which have suffered most during the last two or three years. Their financial resources are heavily depleted and many of them are, in consequence, finding it progressively more difficult to continue. Apart from these mills which face a crisis on account of financial difficulties, there are some others which have come to grief on account of sheer bad or inefficient management. The result of all this is that in any given months some 25 to 30 mills remain closed for various reasons, resulting in loss of production and loss of employment to some thousands of workers. This situation needs to be remedied to the extent practicable and within the resources available, in the interests of the consumer, labour and the shareholder.